(b) and (c) Do not arise, (d) No, Sir.

Regulation of Flow of Water of river Gang*

1170. SHRIMATI BIJOYA CHA-KBAVARTY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the river Ganga is changing its course towards westerly direction at an alarming rate, causing serious threat to Calcutta Port;

(b) if so, what steps are being taken in this regard;

(c) whether it is also a fact that there has been heavy erosion on the right banks to .the Ganga and the river Bhagirathi may be merged with the Ganga causing thereby a massive flow of Ganga water into Bangla-desh; and

(d) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई लोक अदालतें

1171. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार लोक अदालतें आयोजित की गयी हैं ; और

(ख) इन लोक अदालतों की बैठकों में कुल कितने मामलों को अन्तिम रूप से निपटाया गया ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज):(क) और(ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक 520 लोक अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें 5,07,872 मामले निपटाए गए हैं ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1172. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं , और

(ग) इन पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जाएँगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) तारीख 1-8-1988 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों के स्वीकृत 60 पदों में से 12 पद नीचे दी गई तारीखों से रिक्त पड़े हैं :—

अपर न्यायाधीश	स्थायी न्यायाधीश
15-10-84 . .	19-11-87
15-10-84 . .	6-1-88
15-10-84 . .	30-1-88
15-10-84 . .	11-4-88
15-10-84 . .	12-5-88
	1-7-88
	15-7-88

उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार सर्वप्रथम स्थायी रिक्त पद भरे जाते हैं, अतः अपर न्यायाधीशों के उक्त पद रिक्त हैं यद्यपि अक्तूबर, 1984 से स्थायी न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ।

(ख) और (ग) न्यायाधीशों का चयन, सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करके किया जाता है जो एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकार, न्यायाधीशों के रिक्त पदों के शीघ्र भरे जाने का हर संभव प्रयास कर रही है । अतः यह बताना संभव नहीं है कि ये रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश

1173. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस समय कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) इनमें से अल्पसंख्यक समुदायों के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) तारीख 1-8-88 को उपलब्ध अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए) ।

(ख) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

उच्च न्यायालय	1-8-1988 को
1. इलाहाबाद	48
2. आंध्र प्रदेश	19
3. मुम्बई	43
4. कलकत्ता	38
5. दिल्ली	22
6. गुवाहाटी	9
7. गुजरात	16
8. हिमाचल प्रदेश	4
9. जम्मू-कश्मीर	7
10. कर्नाटक	22
11. केरल	20
12. मध्य प्रदेश	26
13. मद्रास	17
14. उड़ीसा	10
15. पटना	28
16. पंजाब और हरियाणा	23
17. राजस्थान	23
18. सिक्किम	2

Closing of CSIR Laboratory at Bhopal

1174. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to close down the Regional Research Laboratory of the CSIR at Bhopal;

(b) if so,- the details thereof; and

(c) whether any action is being taken to provide employment to the affected staff members and scientists?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) No, Sir. The CSIR Society has directed CSIR) to explore the pos-sibil'ty of taking over of the Regional Research Laboratory (RRL). Bhopal, by the Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) or some other Public Sector Undertaking.

(b) and (c) Do not arise.